VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1418)

Name of Candidate	ROSHAN MEENA		
Medium Eng./Hindi	HINDI	Registration Number	4144
Center	HOME	Date	29/12/20

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

[redacted]

EVALUATION INDICATORS

[redacted]

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. Discuss the need to strengthen the National Commission for Scheduled Castes to tackle the problems faced by the Scheduled Castes in India.

(150 words) 10

भारत में अनुसूचित जातियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किया गया।

आयोग में 1 अध्यक्ष एवं 3 सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

वर्तमान में आयोग द्वारा के समक्ष चुनौतियाँ :-

① सलाहकारी प्रकृति का कार्य :

आयोग की सलाह और सलाहकारी होने के कारण अधिक प्रभावी परिणाम नहीं।

② आयोग को सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त इसलिए आयोग जुर्माना, सजा देने जैसे कार्य नहीं कर पाता

③ आयोग में राज्यों का प्रभाव प्रतिनिधि

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

का अभाव। अत: गैर सक्रिय प्रकृति की संरचना।

④ अग्रसक्रीय जाँच एवं स्वयं के वित्तीय स्रोतों का अभाव

⑤ राज्य आयोगों (SC) के पास मानवसंसाधन क्षमता का अभाव, सूचना प्रौद्योगिकी अनुकूल नहीं होने जैसी समस्याएं।

सुझाव: ① महिला सदस्यों की संख्या बढाने की आवश्यकता - ताकि महिला संवेदनशीलता बढ़े।

② आयोग को जुर्माना लगाने की शक्ति प्राप्त हो।

③ आयोग में नियुक्ति की प्रक्रिया समिति आधारित हो।

④ आयोग को अग्रसक्रीय बनाने के लिए मानव संसाधन, वित्तीय सक्षम बनाना।

अत: अनुसूचित जातियों के विरुद्ध हिंसा, बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के आलोक में अग्रसक्रीय प्रणाली आयोग निकाय की जरूरत है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Does the Representation of People's Act ensure an effective mechanism against criminalization of politics in India? Discuss. **(150 words) 10**

क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम भारत में राजनीति के अपराधीकरण के विरूद्ध एक प्रभावी तंत्र सुनिश्चित करता है? चर्चा कीजिए।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा राजनीति के अपराधीकरण को रोकने, चुनावों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने का प्रावधान किया गया है।

प्रभावी तंत्र के रूप में -

① दल बदल आधार पर दलों का विभाजन रोकने के लिए प्रावधान

② अनुच्छेद 123 के तहत भ्रष्टाचार के आधार पर चुनाव जीतने तथा अपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहने को रोकने का प्रावधान।

③ धर्म-जाति के नाम पर वोट मांगने को प्रतिबंधित किया गया है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

④ बलात्कार तथा अन्य ~~सर्विन~~ संगीन अपराधी को चुनाव लड़ने से रोका गया।

⑤ सरकारी सेवाओं में भ्रष्टाचार एवं निष्कासन के आधार पर चुनाव लड़ने से रोकने का प्रावधान किया गया है।

प्रभावी तंत्र सुनिश्चित नहीं करता :-

① ~~वह~~ वोहरा समिति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को अप्रभावी माना तथा इसमें सुधार की मांग की।

② नैतिक संहिता का प्रावधान नहीं है। जिससे नैतिक प्रेरणा का अभाव है।

③ जेल से चुनाव लड़ने की ~~व्यव~~ छूट होना।

④ दल बदल आधार पर चुनाव लड़ने से रोक का अभाव होना।

⑤ लोक लुभावन योजनाओं पर रोक नहीं होना।

अतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संविधान समीक्षा आयोग, तथा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुशंसा अनुसार संशोधन हो।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Discuss the challenges that are being faced by Gram Nyayalayas in their effective functioning. (150 words) 10

ग्राम न्यायालयों द्वारा प्रभावी रूप से कार्य करने में सामना की जा रही चुनौतियों की विवेचना कीजिए।

ग्राम न्यायालयों का गठन वर्ष 2009 में ग्राम न्यायालय अधिनियम के आधार पर किया गया।

ग्राम न्यायालय में प्रथम स्तरीय जिला अधिकारी की अध्यक्षता में संविधान के अनुच्छेद 39 की भावना से 'घर पर न्याय' सुनिश्चित किया जाता है।

चुनौतियां:

(1) राज्यों में असमान क्रियान्वयन - राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में ही ग्राम न्यायालय अधिक सफल हुए हैं।

(2) पदों की रिक्तता तथा मानवसंसाधन का अभाव - जजों की नियुक्ति में राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा देरी होना।

(3) तकनीक को नहीं अपनाना - जिससे न्याय में देरी होना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4) लम्बित मुकदमों की अधिकता – भूमि, परिवार विवाद जैसे मुद्दों की बहुलता।
5) दिन प्रतिदिन आधार पर कार्य नहीं करके सप्ताह के कुछ दिन ही कार्य करना
6) परिवार न्यायालय, ग्राम अदालतों के कारण कार्यों की अस्पष्टता एवं दोहराव।
7) लोगों में न्यायालयों के सम्बंध में जागरूकता का नहीं होना।

अतः आवश्यक है कि वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित की जाए, अखिल भारतीय न्यायिक नियुक्ति का प्रावधान, विशेष प्रोत्साहन, तथा न्याय आपके द्वार (राजस्थान) जैसी पहलों को क्रियान्वित किया जाए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Explain the rationale behind setting up 'Alternative Mechanisms' in ensuring effective decision making in the governance of the country.

(150 words) 10

देश के शासन में प्रभावी निर्णयन सुनिश्चित करने के लिए 'वैकल्पिक तंत्र' स्थापित करने का औचित्य स्पष्ट कीजिए।

'वैकल्पिक तंत्र' का तात्पर्य उस अनौपचारिक तंत्र से है जिसमें पर्याप्त चर्चा, विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा, विशेषज्ञों की भूमिका तथा तीव्रता से निर्णय लेने की क्षमता का विद्यमान होना।'
जैसे नीति आयोग, अनौपचारिक किचन कैबिनेट, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

स्थापना का औचित्य :-

① संसद में स्टेंडिंग समितियां एवं मंत्रिमण्डल समितियों जैसी संरचनाओं में सभी दलों को अपनी बात रखने का अवसर मिल पाता है।

② पर्याप्त चर्चा होने के कारण निर्णय राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते है

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(3) अनौपचारिक तंत्र द्वारा महामारी, राष्ट्रीय आपदा के समय त्वरित निर्णय लेना संभव हो पाता है।

(4) विषयों के विशेषज्ञों की उपस्थिति के कारण तकनीकी जटिलताओं को दूर करना आसान होता है जैसे रक्षा सम्बन्धित निर्णय।

(5) राजनीति से प्रेरित हो वोट बैंक की लोक लुभावन रीति से बचाव हो जाता है।

(6) दक्षता, मितव्ययता, प्रभावशीलता, प्रभावी निर्णयन में सहायक। जैसे कोविड-19 समय स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा निर्णय।

वैकल्पिक तंत्र को केवल पूरक की भूमिका निभानी चाहिए। भारतीय संविधान की सीमाओं में रहकर, जनता के प्रति अंतिम उत्तरदायी रहना, तथा आपदा राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही वैकल्पिक तंत्रों को शक्तियाँ देने चाहिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. The relationship between bureaucracy and democracy is both paradoxical and complementary. Comment. **(150 words) 10**

नौकरशाही और लोकतंत्र के बीच संबंध विरोधाभासी और अनुपूरक दोनों हैं। टिप्पणी कीजिए।

नौकरशाही जहां वेतनीक रोजगार व्रति है वहीं लोकतंत्र एक व्यापक संरचना है

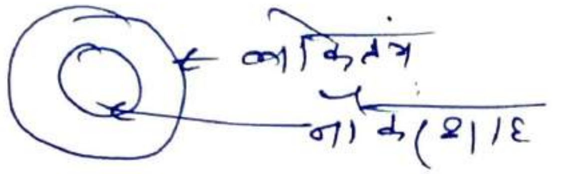

नौकरशाही और लोकतंत्र में विरोधाभासी सम्बंध :-

① वारि. के. अलघ समिति 2003 ने भारतीय नौकरशाही को लोकतंत्र की भावना को दबाने वाला माना।

② नौकरशाही शहरी उन्मुख, वर्ग विशिष्ट, तथा विशिष्ट अभिजात्य मानसिकता का समर्थक है जो गरीबों, ग्रामीणों तथा कमजोरों की उपेक्षा करती है।

③ कार्य को टालना, लालफीताशाही तथा नवाचार का विरोधी होना (P.C होता समिति)

④ पंचायती राज प्रतिनिधियों के प्रति उपेक्षा

Don't write anything in the margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

की मानसिकता का होना (IInd ARC रिपोर्ट)

(5) भ्रष्टाचार को बढ़ाना, भाई भतीजावाद को बढ़ाने वाला।

(6) ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक।

<u>पूरक सम्बंध (लोकतंत्र - नौकरशाही)</u>

(1) सरकार के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए अनिवार्य संस्था के रूप में जरूरी।

(2) वर्तमान जरूरतों अनुरूप स्वयं को ढालने में सक्षम।

(3) कल्याणकारी राज्य का आधार नौकरशाही

(4) सफल उदाहरण - राम स्वरूप → ~~स्वच्छ~~ स्वच्छ भारत अभियान की सफलता में योगदान दिया।

(5) संवैधानिक गणतंत्र की रक्षा, राष्ट्रीय रक्षा हेतु जरूरी

(6) निष्पक्षता, पर्दे के पीछे से कार्य

अतः नौकरशाही में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, मिशन कर्मयोगी के अनुरूप सुधार कर अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. By transforming the way governments work and reinventing people's participation in the democratic process, e-governance empowers the citizen in multiple ways. Discuss in the context of India. **(150 words) 10**
सरकारों के काम करने के तरीके में परिवर्तन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी का पुनर्निर्माण करके, ई-शासन अनेक प्रकार से नागरिकों को सशक्त बनाता है। भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

ई-शासन का तात्पर्य सरकार की कार्य प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी को उपयोग में लाना।

जैसे - e-NAM, e-gov', M-govt, Social media,

ई-शासन का योगदान -

① भौतिक दूरियों को समाप्त करना -
राजस्थान का ई-मित्र पहल, केरल की फ्रेंडस योजना सरकार तथा जनता की भौतिक दूरी मिटा रही है।

② भ्रष्टाचार रोकने, पारदर्शिता में वृद्धि -
- ई-निविदा, ऑनलाइन जारि

③ जवाबदेही में वृद्धि -
स्वत: प्रकटीकरण, RTI के प्रश्नों का

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

④ स्थल स्तर पर सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी, वार्षिक रिपोर्ट की जानकारी जांच। जैसे: 'मेरा अस्पताल' ऐप।

⑤ शिकायत निवारण - इंटरनेट द्वारा प्राप्त शिकायतों की रेल मंत्रालय द्वारा निपटान

⑥ जनता की भागीदारी बढ़ाना - लोक सर्वेक्षण, जनता की ऑनलाइन राय आमंत्रण।

⑦ प्रचार प्रसार हेतु उपयोग - चुनाव आयोग

इस प्रकार भारत में तकनीकी विकास हेतु कॉमन सर्विस सेंटर, डिजिटल भारत, पंचायतों तक भारत नेट की संकल्पना को भी साकार किया जा रहा है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. The Transgender Persons (Protection of Rights) Act 2019 dilutes the spirit of Supreme Court's NALSA judgement towards self-determination of gender. Discuss. (150 words) 10

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 लिंग के आत्मनिर्धारण के प्रति उच्चतम न्यायालय के नालसा (NALSA) निर्णय की भावना को कमजोर करता है। चर्चा कीजिए।

उभयलिंगी व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसकी लिंग पहचान जन्म के समय निर्धारित लिंग पहचान से भिन्न पहचान होती है।

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 एवं उच्चतम न्यायालय के नालसा निर्णय में टकराव -

(1) नालसा निर्णय में लिंग निर्धारण का अंतिम अधिकार जिला स्तरीय चिकित्सा समिति को करने का प्रावधान किया गया था

वर्तमान कानून में जिला अधिकारी को ~~अधि~~ अंतिम अधिकार दिया गया

(2) नालसा वाद में स्वलिंग स्वीकृति को स्वीकार।

जबकि वर्तमान कानून इसको नहीं स्वीकारता।

Don't write anything in the margin

(3) नालसा वाद में शिकायत निवारण समिति का प्रावधान था।

वर्तमान कानून में जिलाधिकारी के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती।

(4) नालसा वाद में रोजगार, शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान था।

वर्तमान कानून इस विषय पर मौन है

(5) नालसा वाद में उभयलिंगी व्यक्तियों को राष्ट्रीय आयोग में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की बात करता है।

वर्तमान कानून में यह प्रावधान नहीं

अतः जरूरी है कि वर्तमान कानून में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय (नालसा) अनुसार संशोधन किये जाये ताकि उपेक्षित, शोषित, पीड़ित समुदाय को पर्याप्त सहारा मिले।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. The worthwhile goal of Universal Health Coverage can be achieved by declaring the right to health as a fundamental right. Comment.

(150 words) 10

स्वास्थ्य के अधिकार को एक मूल अधिकार घोषित करके सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के सार्थक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। टिप्पणी कीजिए।

स्वास्थ्य का अधिकार वैश्विक मानवाधिकार घोषणा पत्र में मूल अधिकार के रूप में वर्णित है।

स्वास्थ्य के अधिकार में – वहनयोग्य स्वास्थ्य सुविधाओं तक सभी की पहुँच को स्वीकार किया जाता है।

स्वास्थ्य के अधिकार को मूल अधिकार घोषित करके निम्न लाभ प्राप्त होंगे →

① राज्य सरकारों पर सभी तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित करने की विधिक बाध्यता का बनाना।

② साथ SGD – लक्ष्य 3 के तहत निर्धारित 2030 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य की सुनिश्चितता संभव होगी।

(3) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भी सार्वभौमिक स्वास्थ्य का लक्ष्य। अतः स्वास्थ्य का अधिकार जरूरी।

(4) न्यायिक प्रणाली द्वारा राज्यों की जवाबदेही सुनिश्चित हो जा सकेगी।

(5) मानवीय गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(6) मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर कुपोषण की कमी संभव। जिससे 'HDI' सूचकांक में भारत की रैंक सुधरेगी।

(7) स्वस्थ कार्मिक 'जनांकिकी लाभांश' की पूर्व शर्त।

(8) लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक न्याय के लिए जरूरी।

इस प्रकार संविधान अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य के अधिकार को मूलाधिकार घोषित किया जा सकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. Indian Diaspora in the Gulf countries is an asset beset with multiple challenges. Comment. **(150 words) 10**
खाड़ी देशों में भारतीय डायस्पोरा अनेक चुनौतियों से घिरी एक परिसंपत्ति है। टिप्पणी कीजिए।

खाड़ी देशों में भारत के 1.1 करोड़ लोग (डायस्पोरा) विद्यमान है [विदेशमंत्रालय]

ये अकुशल - कुशल श्रमिक, सेवा क्षेत्र में अपनी सेवा देते है।

विद्यमान चुनौतियाँ :-

① स्थानिय कानूनों के कारण चुनौतियां -
खाड़ी अरब का तिनाकत कानून, कतर का घरेलू श्रमिक वरियता कानून।

② नियोक्ताओं द्वारा शोषण -
मानवाधिकारों का उल्लंघन, निकृष्ट प्रकृति के कार्यों में नियोजन।

③ सामाजिक सुरक्षा का अभाव होना -
पेंशन, वेतन अनिश्चित, बीमा सुविधा का अभाव।

④ बिचौलियों द्वारा शोषण -
वीजा नियमों का उल्लंघन करना

Don't write anything in the margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(5) आवासी चुनौतियां, कल्चर में अन्तर के कारण जेल में डालने जैसी घटनायें।
(6) श्रम संघों का अभाव होना।

<u>सरकारी प्रयास:</u>
① महात्मा गांधी प्रवासी कामगार सुरक्षा योजना
② द्विपक्षीय स्तर पर वार्ता- ईरान, सऊदी अरब से।
③ प्रवासी सुरक्षा योजना।
④ प्रवासी दिवस का आयोजन
⑤ आपरेशन 'राहत'

इस प्रकार 88 बिलियन विप्रेषण भेजने, भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के कारण इन कामगारों की महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. Briefly outline the genesis and functioning of World Food Programme (WFP). Also highlight its contribution to India's effort in addressing the issue of hunger and malnutrition. **(150 words) 10**

विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) की उत्पत्ति और कार्यप्रणाली की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। साथ ही, भूख और कुपोषण की समस्या को दूर करने के भारत के प्रयासों में इसके योगदान पर भी प्रकाश डालिए।

'विश्व खाद्य कार्यक्रम' की योजना विश्व खाद्य आयोग द्वारा की गई।

इसके प्रमुख दर्शन -

① भुखमरी को जड़ से समाप्त करने में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग।

② मानवाधिकार के रूप में खाद्यान्न के अधिकार की रक्षा।

कार्यप्रणाली -

① वित्तीय प्रोत्साहन - द्वारा विकासशील एवं गरीब देशों को खाद्यान्न की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना।

② आपदा के समय विशेष सहयोग।

③ कृषि तकनीकी सहयोग के लिए

प्रभाव

④ विकसित देशों के बाजारों से रक्षा

भारत में योगदान -

① 'गोल्डन राइस' के रूप में विटामिन (A) युक्त चावल की भारत में आपूर्ति

② फोर्टिफाइड खाद्यान्न के लिए भारत को सहयोग देना।

③ तकनीकि सहयोग प्रदान करना जैसे आपदा चेतावनी, नई उभरती तकनीकों में मदद।

④ भारत द्वारा अफ्रीकी देशों में इसी कार्यक्रम के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति कोविड महामारी दौरान की गई।

इस प्रकार विश्व खाद्यान्न कार्यक्रम 2030 तक गरीबी भुखमरी को समाप्त करने का लक्ष्य लिये हुए है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Action against civil society groups is seen as shrinking space for dissent by some while others point out to the imperatives of merit based action against certain groups. Examine with examples. **(250 words) 15**

कुछ लोगों द्वारा नागरिक समाज समूहों के विरूद्ध कार्रवाई को असहमति के लिए कम होती स्वीकार्यता के रूप में देखा जाता है, जबकि अन्य लोग कतिपय समूहों के विरूद्ध गुणावगुण आधारित कार्रवाई की अनिवार्यता की ओर इंगित करते हैं। उदाहरण सहित परीक्षण कीजिए।

नागरिक समाज समूह के औपचारिक-अनौपचारिक समूह होते है जो स्वप्रेरणा से लोगों के लिए कार्य करते है। जैसे 'सेवा' समूह द्वारा नारी सशक्तिकरण

नागरिक समूहों के विरूद्ध हाल में कार्यवाहियां की है —

① विदेशी अनुदान अधि० 2010 का कठोर क्रियान्वयन

② IB रिपोर्ट में देश विरोधी कार्यों का आरोप

③ गृह मंत्रालय द्वारा 2014-2019 मध्य 19000 (लगभग) 'NGO' को प्रतिबंध लगाना

कार्यवाहियों को असहमति कम होती स्वीकृति

① नागरिक अधिकार संगठनों द्वारा

देश विरोधी कार्यवाहियों में शामिल होने का आरोप लगाना - जैसे ग्रिनपीस कुनडलकुलम परियोजना का विरोध।

② वित्तीय प्रकटीकरण का अभाव - सुप्रीम कोर्ट में मात्र 10% ने ही अपना वार्षिक विवरण दायर किया।

③ शीर्ष कम्पनी का ढाँचा, काले धन को सफेद में बदलने की भूमिका में संलिप्तता

④ केवल शिक्षा, स्वास्थ्य तक सीमित होना

⑤ मानवसंसाधन का अभाव तथा तकनीकि पिछड़ापन का होना।

⑥ युवाओं की 'NGO' में कम रुचि का होना।

⑦ विशेषज्ञता तथा दक्षतापूर्ण कार्य का अभाव

गुणवत्ता आधारित कार्यवाहियाँ =

① सुप्रीम कोर्ट निर्देशों तथा गृह

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

मंत्रालय की कार्यवाहियाँ केवल देश के नुकसान पहुँचाने वाले समूहों के विरुद्ध ही थी।

(3) अभी भी प्रति 600 लोगों पर एक नागरिक संगठन संक्रिय होना।

(3) टाटा ट्रस्ट, गेट्स फाउंडेशन, 'ADR' जैसे प्रभावशाली नागरिक समूह सक्रिय स्थिति में

(4) अन्य :- लोकपाल अधिनियम, FCRA संशोधित अधिनियम 2018, तथा RTI अधि० के माध्यम से पारदर्शिता का प्रयास किया गया है।

(5) सोशल ऑडिटिंग, कोविड-19 महामारी, सर्व प्रति पुष्टि हेतु अभी भी ये समूह सरकार के सहयोगी के रूप में कार्यशील

अतः लोकतांत्रिक, पारदर्शिता, प्रभावशीलता के लिए नागरिक संगठनों में सुधार के प्रयासों का स्वागत किया जाना चाहिए।

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ न लिखें)

12. Discuss the implications associated with the Prime Minister's Office acting as the most powerful office due to its formidable influence in policymaking in India. **(250 words) 15**

भारत में नीति-निर्माण में अपने अत्यधिक प्रभाव के कारण प्रधान मंत्री कार्यालय के सर्वाधिक शक्तिशाली कार्यालय के रूप में कार्य करने से संबद्ध निहितार्थों की विवेचना कीजिए।

प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना 1965 उपरांत प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के कार्यकाल में की गई थी।

यह एक सलाहकारी कार्यालय है जो विभिन्न मुद्दों पर प्रधानमंत्री के कार्यों के क्रियान्वयन में सहायता उपलब्ध करवाता है।

नीति-निर्माण में अत्यधिक प्रभाव

1. अधिकतर निर्णय इसी कार्यालय द्वारा लिये जाते हैं।
2. विभिन्न मंत्रालयों विभागों को यह निर्देश जारी करता है तथा उनसे रिपोर्ट मंगाता है।
3. प्रधानमंत्री को विभिन्न मुद्दों पर सलाह देना, तथा अवगत करवाना।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(4) पद सोपान क्रम में इसका स्थान अत्यन्त ऊपर होना [हालांकि इसका गठन किसी संवैधानिक आदेश से नहीं हुआ।

निहितार्थ :

① प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा शक्तियों का संकेन्द्रण करने के कारण लोकतंत्र की भावना का उल्लंघन होता है।

② प्रधानमंत्री कार्यालय में जवाबदेही तंत्र का अभाव है। इसलिए कार्यालय को किसी तरह से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

③ 'सूक्ष्म' कार्यालय होते हुए भी 'स्टॉफ' कार्यों में दखल देने का आरोप लगना

④ प्रधानमंत्री कार्यालय की अपारदर्शी कार्यप्रणाली।

⑤ मंत्रीमण्डल सचिवालय की भूमिका का सीमित होना।

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सुझाव:

① प्रधानमंत्री कार्यालय को संवैधानिक आधार देते हुए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

② संविधान समीक्षा आयोग ने भी प्रधानमंत्री कार्यालय के पास बढ़ती शक्ति पर आपत्ति प्रकट की तथा मंत्रिमण्डल को शक्ति केंद्र बनाने की सलाह दी।

③ प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचना का अधिकार, संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सकता है।

अतः आवश्यक है कि प्रधानमंत्री कार्यालय अपने सलाहकारी प्रकृति का ही कार्य करे और मंत्रिमण्डल संविधानानुसार को प्रमुख रूप से प्रभावशाली बना लोकतंत्र में शक्ति प्रत्यक्षण सुनिश्चित किया जाए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. While judiciary's efforts to infuse accountability in the functioning of government institutions and engender human rights jurisprudence demonstrate the importance of judicial governance, it also leads to concerns around judicial overreach. Discuss. **(250 words) 15**
जहाँ सरकारी संस्थानों के कार्यकरण में जवाबदेही का संचार करने और मानवाधिकार न्यायशास्त्र उत्पन्न करने का न्यायपालिका का प्रयास न्यायिक शासन का महत्व प्रदर्शित करता है, वहीं यह न्यायिक अतिक्रमण के चतुर्दिक चिंताओं को भी जन्म देता है। चर्चा कीजिए।

न्यायिक शासन संविधान के अनुच्छेद 39(A) तथा अनुच्छेद 124-147 से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। पूर्ण न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के अनुच्छेद 13, 31 का भी सहारा लिया जाता है।

जवाबदेही (कार्यपालिका) में योगदान :

① अपनी रीट अधिकारों का प्रयोग करते हुए (अनु० 32, 226) न्यायपालिका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेशों द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाये रखती है।

② दिल्ली सिलिंग आदेश, चुनाव सुधार सम्बंधित निर्णय तथा न्याय

फाउंडेशन वाद, 'LGBTQ' समुदायों को आरक्षण देने, दिव्यांगों को आरक्षण देने जैसे आदेश कार्यपालिका को जवाबदेही बनाते हैं।

③ ~~चुनाव आयोग~~ कार्यपालिका को विधिक क्रियान्वयन का निर्देश तथा भ्रष्टाचार को नियंत्रण का निर्देश।

किंतु न्यायपालिका न्यायिक अतिक्रमण से भी ग्रस्त है।

न्यायिक अतिक्रिया:

① PIL वादों की बढ़ती आवृत्ति के कारण न्यायपालिका अपने क्षेत्र का विस्तार करने लगा है।

② न्यायपालिका में 3.5 करोड़ वादों का लंबित होना [न्यायिक डाटा ग्रिड रिपोर्ट]

③ विधि निर्माण का कार्य विधायिका का कार्य है। न्यायपालिका की आलोचना है तथा आदेशों में विधिक दिशानिर्देश

निर्धारण करने का अधिकार नहीं

(4) विधि आयोग ने न्यायपालिका को केवल विधिक प्रश्नों पर निर्णय देने को कहा।

(5) न्यायपालिका की व्याख्या जटिल जब तकनीकी प्रश्नों पर उसके द्वारा निर्णय दिया जाता है।

(6) संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत शक्ति पृथक्करण का पालन न्यायपालिका को करना होगा।

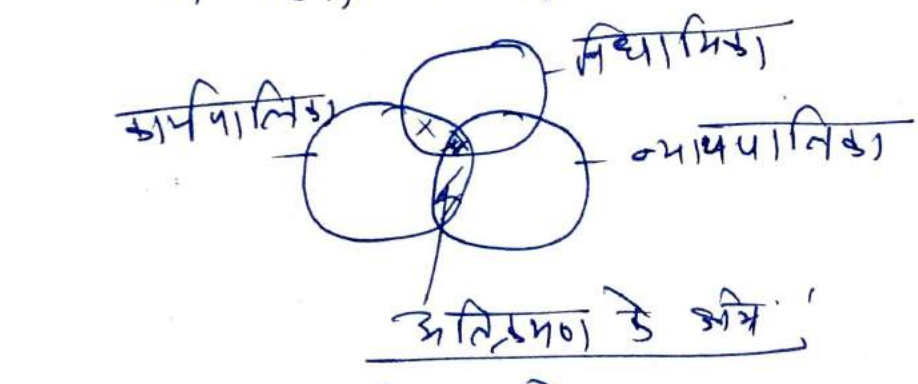

अतिक्रमण के क्षेत्र

अतः न्यायपालिका को PIL, तथा स्वतः संज्ञान केवल राष्ट्रीय हित तथा विधिक आधारों पर ही करना चाहिए तथा लम्बित वादों के निस्तारण पर बल देना चाहिए।

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. The power to punish for contempt of court is necessary for the administration of justice. Critically analyse. **(250 words) 15**
न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति न्याय के प्रशासन के लिए आवश्यक है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

न्यायालय की अवमानना को संविधान अनुच्छेद 19(2) अपवाद खण्ड, 215, 129 में प्रावधान किया गया है। न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 इसके सम्बंध में प्रावधान करता है

न्यायिक अवमानना

सिविल अवमानना
- न्यायिक आदेशों को नहीं मानना

आपराधिक अवमानना
- न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप
- न्यायालय छवि बिगाड़ना

न्यायिक अवमानना पर 3 माह जेल या 2000 रुपये जुर्माने का प्रावधान।

न्याय अवमानना की जरूरत:

① विधि आयोग अनुसार न्याय अवमानना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा मुद्दा नहीं बल्कि अधीनस्थ न्यायालयों को प्रभावशाली

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

बनाने के लिए लिए जरूरी |

② 'न्याय का शासन' सुनिश्चित करने के लिए अवमानना की आवश्यकता

③ न्यायिक न्यायिक छवि की रक्षा, जनता का न्याय प्रणाली में विश्वास हेतु न्यायिक दण्ड की जरूरत |

④ भारत में न्यायिक अवमानना की बढ़ती संख्या के कारण कानून की प्रासंगिकता बनी हुई है

⑤ न्यायालय यह शक्ति संविधान से प्राप्त करता है अतः संविधान निर्माताओं की भावनाओं के अनुरूप प्रयोग होना |

⑥ न्यायिक अवमानना के लिए दण्ड का प्रावधान न्यायिक कार्यों को बिना भय, दबाव के सुचारु रूप से क्रियान्वित करने में मदद करता है

विपक्ष में तर्क: ① इंग्लैण्ड, कनाडा में समाप्त

Do, anythi (इस कुछ बा

अतः विश्व के उदाहरणों अनुरूप इसे भी समाप्त कर देना चाहिए।

② न्यायिक अवमानना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनु० 19(1) का उल्लंघन करती है।

③ न्यायिक अवमानना का प्रयोग प्रशासन की दक्षता कार्यक्षमता में दखल प्रभावित करने का कार्य करता है जैसे सुरक्षा बल नियुक्ति

④ परिभाषा अस्पष्ट – अन्य विधियों से जैसे शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं

⑤ सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र आलोचना, न्यायिक निर्णयों की गुणवत्ता पर मूल्यांकन को छूट दी वहीं अन्य निर्णयों में विपरीत निर्णय – अतः विरोधाभासी निर्णय।

⑥ वर्तमान लोकतांत्रिक समाज अनुकूल नहीं

अतः न्यायिक अवमानना को जारी रखना चाहिए ताकि न्याय का शासन सुनिश्चित हो साथ ही अस्पष्ट परिभाषा, निष्पक्ष आलोचना तथा न्यायिक सुधारों को पूर्णतः लागू किया जाना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. What are the legal concerns associated with custodial violence? Discuss the challenges in curbing such incidents. Also, suggest some ways to address this issue. **(250 words) 15**

अभिरक्षा में हिंसा से संबद्ध विधिक चिंताएं क्या हैं? ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने में सामने आने वाली चुनौतियों की विवेचना कीजिए। साथ ही, इस समस्या का समाधान करने हेतु कुछ उपायों का भी सुझाव दीजिए।

हाल ही में तमिलनाडु में एक पिता एवं उसके पुत्र की पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हो गई। इस कारण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हुई।

विधिक चिंताएँ –

(1) भारत विश्व में सर्वाधिक अभिरक्षा में हिंसा वाला देश के रूप में उभरा।

(2) मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा तथा भारतीय संविधान के अनु० 21, 22 की भावना का उल्लंघन होना।

(3) पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगाना।

(4) NCRB रिपोर्ट अनुसार अभिरक्षा में बलात्कार, तथा शोषण की दर लगातार बढ़ रही है

Don't write anything in this margin

+ अंकुश लगाने में सामने आने वाली चुनौतियाँ

① पुलिस राज्य सूची का विषय अतः पुलिस सुधारों (प्रकाश सिंह वाद 2006) को लागू करने में देरी।

② 1860 का पुलिस कानून जो वर्तमान स्वतंत्र भारत की भावनाओं के लिए अनुपयुक्त है।

③ पुलिस पर राजनैतिक दबाव एवं पुलिस का राजनैतिक उपयोग होना (पुलिस सुधार आयोग 1978)

④ पुलिस बलों में मानवाधिकारों की जानकारी एवं प्रशिक्षण का अभाव।

⑤ ~~[illegible]~~ पुलिस बलों में अत्यधिक कार्यभार तथा मानसिक तनाव, कम वेतन, भ्रष्टाचार

⑥ न्याय में देरी, जनता का त्वरित न्याय के प्रति लगाव का होना।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

उपाय

① प्रकाश सिंह वाद 2006 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को शब्दशः लागू करना।

② साक्ष्य आधारित पुलिस हेतु फोरेंसिक लैब. तथा विशेषज्ञ पूर्ण प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।

③ पुलिस संवेदनशीलता हेतु 33% महिला पुलिस की अनिवार्यता - आरक्षण द्वारा

④ पुलिस सुधार आयोग की रिपोर्ट को लागू करना ताकि पुलिस प्रशिक्षण प्रणाली के वेतन भत्तों को बढ़ावा मिले।

⑤ मलिमथ समिति की सिफारिशों अनुरूप पुलिस जांच प्रणाली तथा

⑥ न्यायिक सुधार द्वारा तीव्रता से निपटान

अतः स्मार्ट पुलिस, समुदाय पुलिस, CCTV कैमरों का थानों में लगाना, जवाबदेही के लिए राजनैतिक दखल से मुक्ति जैसे प्रयासों की सख्त जरूरत है।

Don't write anything in this margin (इस ... कुछ ...)

16. Civil society interventions, ranging from confrontation to engagement with the government, have played an important role in ushering transparency and accountability in governance in India. Discuss with examples.

(250 words) 15

सरकार के साथ टकराव से लेकर जुड़ाव तक सिविल सोसाइटी के हस्तक्षेपों ने भारत में शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही का सूत्रपात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए।

सिविल सोसायटी लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ होता है। इसमे NGO, गैर लाभकारी संगठन, श्रम संगठन, किसान संगठन, कर्मचारी संगठन, SHG जैसे सभी औपचारिक अनौपचारिक समूह सम्मिलित होते है।

सिविल सोसायटी द्वारा शासन प्रणाली मे पारदर्शिता एवं जवाबदेही हेतु अनेक प्रयास किये है।

सरकार के साथ जुड़ाव द्वारा –

① ऊर्जा रक्षण करने मे – टेरी (TERI) द्वारा ऊर्जा क्षेत्र मे भारत की समृद्ध ऊर्जा प्रणाली मे अपना तकनीकी योगदान दिया जाता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(2) पर्यावरण संरक्षण में सुधार हेतु - WWF, सलीम अली पक्षी अनुसंधान, ~~वरवर वर्ष~~ ग्रीनपीस अन्तर्राष्ट्रीय द्वारा सरकार के कार्यों में मदद की जाती है।

(3) सूचना का अधिकार - मजदूर किसान संगठन द्वारा सूचना के अधिकार को लागू करने हेतु सरकार पर दबाव बनाया गया।

(4) लोकपाल कानून - अन्ना हजारे के नेतृत्व में लोकपाल कानून को पारित किया गया।

(5) न्यायिक प्रणाली में - 'ADR' जैसी संस्थाने संसद तथा न्यायपालिका सुधार हेतु सक्रीय

टकराव (1) नर्मदा बचाओ आंदोलन बांधो की लम्बाई (ऊंचाई) से जनजातीय लोगों की रक्षा हेतु

Don't write anything in this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

② अखिल भारतीय किसान संगठन 'MSP' को लेकर सरकार से टकराव।

③ चिपको आंदोलन पेड़ों की रक्षा हेतु प्रशासन से टकराव।

④ कुडनकुलम परियोजना विरोध के द्वारा पारदर्शिता परमाणु ऊर्जा तकनीक में सुधार

⑤ अन्य - जनजातीयों के लिए कार्य करनेवाले

इस प्रकार सरकार को जवाबदेही बनाने तथा प्रशासन को अति सक्रीय रखने में नागरिक संगठनों द्वारा धरनों विरोध प्रदर्शन तथा सहयोगी कार्य जैसे सभी तरीकों को अपनाया जाता है। जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. When it comes to hunger, India faces the paradox of plenty. Discuss. Also suggest ways in which this concern can be addressed. (250 words) 15

जब भुखमरी की बात आती है, भारत को प्रचुरता के विरोधाभास का सामना करना पड़ता है। चर्चा कीजिए। साथ ही, उन उपायों का भी सुझाव दीजिए, जिनके माध्यम से इस चिंता का समाधान किया जा सकता है।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स अनुसार भारत में 19.3 करोड़ लोग अत्यन्त भुखमरी का सामना कर रहे है।

भुखमरी वह स्थिति है जब किसी व्यक्ति को 2900 कैलोरी और 60 ग्राम प्रोटिन प्रतिदिन नहीं मिलता — 'WHO'

भारत में विरोधाभासी स्थिति:

① भारत में खाद्यान की प्रचुरता फिर भी वितरणमूलक न्याय के अभाव में खाद्यान तक पहुँच का अभाव

② भौतिक पहुँच, वित्तीय पहुँच की चुनौती का होना।

③ सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण छुपी भूख (हिडन हंगर) की स्थिति। भी

④ भारतीयों को 'WHO' अनुसार 2400 कैलोरी तथा 30 ग्राम औसत प्रोटीन प्रतिदिन ही

(5) 50% महिलाओं में रक्तीमता (NFHS-4)

(6) वहीं जनजातीय लोगों को औसत 1700 (लगभग) कैलोरी भोजन की।

(7) शहरी क्षेत्रों में ओवरवेट की बढ़ती प्रवृत्ति।

(8) पतला दिखने की चाह में कम वजन की नई प्रवृति - सम्पन्न परिवारों में

(9) ठिगनापन - 38%, दुबलापन 20.7%

उपाय :-

(1) मध्याह्न भोजन में मोटे अनाज स्थानिय उत्पादों को बढ़ावा देना।

(2) खाद्य वितरण प्रणाली में दाले, तेल जैसे उत्पादों को समावेश करना।

(3) स्कूली शिक्षा में अच्छे स्वास्थ्य भोजन सम्बन्धित जागरूकता को बढ़ाना।

(4) फूड फोर्टिफिकेशन, गोल्डन राइस

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

बीटी फसलों को बढ़ावा देने का प्रयास

(5) भोजन के साथ-साथ स्वच्छता, मानसिक तनाव से मुक्ति, वित्तीय सशक्तिकरण को अनिवार्य जोड़कर रखना।

(6) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण द्वारा लोगों को सशक्त करना।

(7) खाद्यान्न व पौष्टिक उपलब्धता हेतु खाद्यान्न वितरण व सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला पर बल देना।

(8) सरकारी कार्यक्रमों का पालन करना -
(1) ICDS (2) अन्त्योदय योजना (3) एक देश एक राशन कार्ड (4) प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (5) महिला सशक्तिकरण
(6) टीकाकरण कार्यक्रम इत्यादि।

अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम 2013 का पालन किया जाना चाहिए ताकि जनांकिकीय लाभांश का लाभ उठाया जा सके।

Don't write anything in the margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. What is the role of wage employment in alleviating poverty? How is the MGNREGA different from the earlier Wage Employment Programmes in India?

(250 words) 15

निर्धनता उन्मूलन में मजदूरी रोजगार की क्या भूमिका है? मनरेगा (MGNREGA) भारत में पहले के मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों से कैसे भिन्न है?

भारत मे तेंदुलकर समिति अनुसार 21.9% लोग निर्धनता रेखा से नीचे जीवन-यापन करते है। साथ ही 19.4 करोड़ लोग अत्यन्त निर्धन है [विश्व बैंक]।

निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा खाद्यान सुरक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम तथा पेंशन जैसे तरीको को अपनाती है।

मजदूरी रोजगार की भूमिका -

मजदूरी का अधिकार देकर रोजगार तथा निर्धनता उन्मूलन जैसे दोहरे लक्ष्यों के साथ मनरेगा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(1) इससे रोजगार की प्राप्ति होती है जिससे व्यक्ति की क्षमता का उपयोग

परिसम्पत्तियों के निर्माण में किया जाता है।

(2)

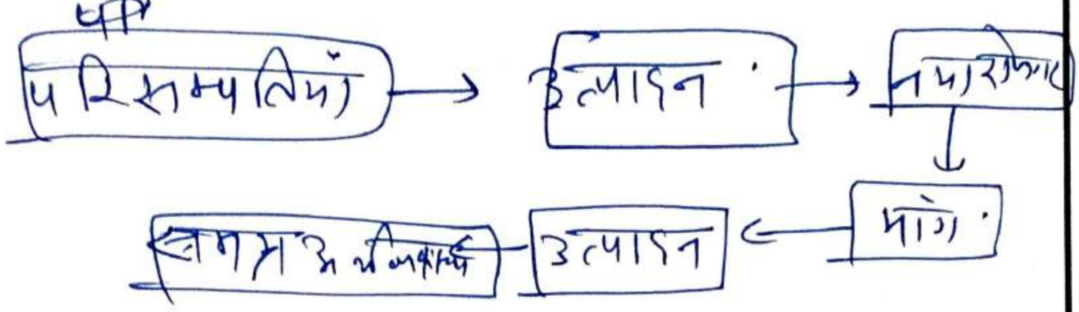

(3) व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि होती है

(4) रोजगार व्यक्ति को खर्च करने की स्वायत्तता प्रदान करता है।

+ मनरेगा पहले के कार्यक्रमों से भिन्न

(1) जवाहर रोजगार योजना, काम के बदले अनाज जैसे कार्यक्रमों में रोजगार की कानूनी गारंटी प्राप्त नहीं थी। मनरेगा में न्यूनतम 100 दिन काम के बदले गारंटी प्राप्त है।

(2) पूर्व के कार्यक्रमों में न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान नहीं था।

मनरेगा में राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम भुगतान की गारंटी प्राप्त है।

③ पूर्व के कार्यक्रमों में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त नहीं था।

मनरेगा में न्यूनतम 33% आरक्षण प्राप्त।

④ मनरेगा नकद खाते में भुगतान की व्यवस्था करता है। तथा पूर्णतः डिजिटल जीओ टैगिंग का प्रावधान है।

⑤ मनरेगा में सोशल ऑडिटिंग का का प्रावधान इसे भिन्न बनाता है।

अतः संयुक्त राष्ट्र संघ ने मनरेगा को विश्व की सबसे सफल गरीबी निवारण कार्यक्रम के रूप में चयनित किया।

19. China's aggressiveness in recent times presents not only challenges to India but also opportunities to strengthen itself internationally and domestically. Discuss. **(250 words) 15**

हाल के दिनों में चीनी आक्रामकता न केवल भारत के लिए चुनौतियां खड़ी करती है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर अपने आपको सशक्त बनाने का अवसर भी प्रदान करती है। चर्चा कीजिए।

डोकलाम घुसपैठ, सियाचिन में चीन द्वारा सैनिकों की उपस्थिति बढ़ाना, तथा गालवान घाटी में सैन्य टकराव के परिप्रेक्ष्य में भारत के समक्ष चीन चुनौती प्रस्तुत कर रहा है।

चीन एवं भारत के मध्य टकराव

① सीमा विवाद -

सीमा चीन तथा अरुणाचल प्रदेश के सीमाओं को लेकर भारत एवं चीन के मध्य टकराव विद्यमान।

चीन जहां कुल सीमा 2000 किमी मानता है वहीं भारत अनुसार 3488 किमी कुल सीमा है।

② सैन्य बलों की बढ़ती गतिविधियां

सियाचीन में चीन द्वारा अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई।

Don't write anything in the margin (इस भाग में कुछ न लिखें)

③ स्ट्रींग ऑफ पर्ल्स की चीन की नीति - भारत के चारो तरफ बंदरगाह बनाकर घेरने की नीति। उदाहरण ग्वादर, क्योकप्यू

④ दक्षिण चीन सागर में भारतीय तेल उत्खनन को रोकना।

⑤ हिंद महासागर में चीन की बढ़ती सैन्य पनडुबियां।

भारत के पास अवसर (सशक्त करे)

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर:

① मालदीप को 1.3 बिलियन का ऋण देकर चीन के ऋण जाल से मुक्त कर भारत ने पुनः अपने आप को सशक्त किया है।

② चीन की बढ़ती आक्रमता को सबके सामने लाकर श्रीलंका, अफ्रीकी देशों को सतर्क करना। हबनटोटा को चीन द्वारा 99 वर्ष हेतु लिज पर लेना इसका उदाहरण।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

③ भारत द्वारा चाबाहार, दुकम जैसे बंदरगाहों का निर्माण करना।

④ अमेरिका को, S-400 रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए समर्थन में लेना

⑤ क्वाड समूह निर्माण कर हिंदमहासागर प्रशांत सागर में अपने आप को आगे बढ़ाना।

⑥ नेपाल, बांग्लादेश जैसे के साथ पुनः रिश्ते सुधारना

घरेलु स्तर पर संशाधन

① दो मोर्चों पर युद्ध के लिए सेना को तैयार करना।

② सीमा पर अवसंरचना, सड़क निर्माण का अवसर।

③ चीन के आर्थिक आक्रमकता को रोकने हेतु आत्मनिर्भर भारत, चीनी एप्प प्रतिबंध

④ घरेलु उत्पादन को बढ़ाना।

अतः भारत द्वारा घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं।

Don't write anything in the margin

20. Trade and connectivity hold the key for India to better engage its neighbours. Examine the opportunities and challenges in South Asia in this context. (250 words) 15

व्यापार और कनेक्टिविटी, भारत के लिए अपने पड़ोसियों से बेहतर तरीके से जुड़ने का सामर्थ्य रखती है। इस संदर्भ में दक्षिण एशिया में अवसरों और चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।

सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी तथा पड़ोसी प्रथम नीति के तहत व्यापार एवं कनेक्टिविटी का भारत के पास व्यापक अवसर विद्यमान है।

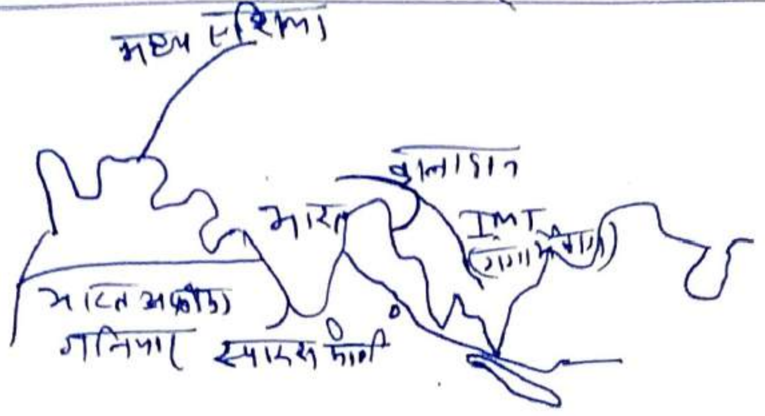

द. एशिया में अवसर है -

① मोटर व्हीकल समझौते द्वारा परिवहन का स्वतंत्र एवं मुक्त मार्ग खोलना आसान — वर्तमान में भारत - नेपाल - बांग्लादेश - तथा भूटान ने हस्ताक्षर किये हैं।

② अन्तर्राष्ट्रीय क्रास सड़क रेल मार्ग

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

दक्षिण एशिया से गुजरेगा जो दक्षिण एशिया के लिए व्यापक सकारात्मक।

(3) कालादान मल्टीमॉडल द्वारा उत्तरपूर्वी राज्यों से जुड़ने का अवसर।

(4) भारत – ~~म्यांमा~~ म्यांमार – थाइलैण्ड सड़क-रेल तथा पाइपलाइन द्वारा जुड़ाव का व्यापक अवसर

(5) 'IORA-RC' तथा 'सागर' परियोजना मौसम परियोजना, ब्लू सिल्क रूट द्वारा पुराने (प्राचीन मार्गों को खोलने का अवसर

चुनौतियाँ :

(1) दक्षिण एशिया देशों का आपसी व्यापार मात्र 5% है [IMF]

(2) आम सहमती का अभाव – जैसे भूटान द्वारा BBIN से बाहर होना

(3) वित्तीय का अभाव के कारण यु.

(4) परियोजना क्रियान्वयन में देरी –
कालापानी मल्टीमॉडल

(5) पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद फैल

(6) दक्षिण एशिया के देशों द्वारा
भारत पर 'बड़े भाई' की भूमिका
आरोप लगाना।

(7) भौगोलिक जटिलता – दलदल

(8) समुद्री डाकुओं की समस्या।

(9) कोविड –19 उपरांत व्यापार संकु

अतः इन सभी समस्याओं को
दूर करने की आवश्यकता है।